

आरसीईपी व्यापार संधि भारत के लिये वनिाशकारी हो सकती है : नीतिआयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीतिआयोग ने कषेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में भारत के शामिल होने पर नकारात्मक परणामों की ओर संकेत दिया है और यह भी कहा है कि भारत को इसमें शामिल होने पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि चीन इसमें मुख्य खिलाडी की भूमिका में है, अतः भारत का हति इससे बाधति होगा ।

कषेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) क्या है?

- यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है । इसमें एशिया-प्रशांत कषेत्र के 16 देश शामिल हैं । इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है ।
- इसमें शामिल कुल 16 देशों में आसियान के 10 सदस्य देश तथा 6 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड हैं ।
- सदस्य देश : ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वयितनाम ।
- इनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं ।
- वस्तुतः आरईसीपी वार्ता की औपचारिक शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजति 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हो गई थी ।
- आरईसीपी को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है ।
- आरसीईपी में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25%, वैश्विक व्यापार का 30%, वदिशी प्रत्यक्ष निवेश का 26% (एफडीआई) तथा कुल आबादी का 45% निवेशति है ।

वरोध के प्रमुख मुद्दे

- नीतिआयोग का कहना है कि व्यापार समझौते का आशय द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है ताकि दोनों पक्ष समान रूप से लाभान्वति हों ।
- एशिया प्रशांत कषेत्र के बाजारों में भारत-चीन के इस सहयोग का प्रमुख परणाम संभवतः अधिकांश कषेत्रों में चीन की क्षमता में वृद्धिसे आयात की बढ़ोतरी के रूप में हो सकती है ।
- एक और प्रमुख मुद्दा चीनी बाजारों में भारतीय निर्यात की बहुत सीमति पहुँच है, जिसके कारण भारत को व्यापक नुकसान झेलना पड़ सकता है ।
- ध्यातव्य है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसकी कुल व्यापार में लगभग 10% की हसिसेदारी है ।
- वतित वर्ष 2012 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार सरिफ 1.8 अरब डॉलर था जो बढ़कर वतित वर्ष 2014 में 72 अरब डॉलर हो गया ।
- चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 52 अरब डॉलर है, जो कुल व्यापार घाटे का लगभग आधा हसिसा है ।

आगे की राह

- कोरिया और जापान के साथ भारत का पहले से ही द्विपक्षीय एफटीए है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय एफटीए की बातचीत भी चल रही है अतः इन देशों के साथ अपने संबंध को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है ।
- साथ ही, आरसीईपी समझौते के साथ आगे बढ़ते समय हमें भूगर्भीय मुद्दों को भी ध्यान में रखना चाहयि क्योंकि इसका परणाम संपूर्ण एशिया-प्रशांत कषेत्र का बाजार अपने वरोधी चीन को सौंपने के रूप में सामने आ सकता है ।
- इसके अलावा भारत को कुछ नवीन कदमों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे- सेवाओं के उदारीकरण पर बल देना, जिसमें अल्पकालिक कार्य के लिये पेशेवरों के आने-जाने के नियमों को आसान बनाना शामिल है ।